



भारत का गज़त The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 1980/कार्तिक 21, 1902

No. 215]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 1980/KARTIKA 21, 1902

इस भाग में वित्त पृष्ठ संख्या खीं जाती है जिससे इस अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

बाणिज्य मंत्रालय

आयात आपार, नियन्त्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 43—आईटीसी (पी एन) /80

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1980

विषय : 1980-81 के प० जर्मनी पूँजीगत माल केंद्रित से संबंधित लाइसेंस ग्राहक।

मिसिल सं० आईटीसी/23/(10)/80 :— 1980-81 के लिए प० जर्मनी पूँजीगत माल केंद्रित के अधीन आयात लाइसेंसों के नियन्त्रण को नियन्त्रित करने वाली जो ग्राहक इस सार्वजनिक सूचना के परिचय में दी गई है, सूचना के लिए अधिसूचित की जाती है।

मणि नारायणस्त्री,

मुख्य नियन्त्रक, आयात-नियन्त्रण

बाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 43—आईटीसी (पी एन) /80, दिनांक 12-11-80 का परिचय।

1980-81 के लिए 4 करोड़ 40 लाख डी० एम० के परिचयी जर्मनी पूँजीगत माल केंद्रित के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों से संबंधित ग्राहक।

1. (1) जिस मामले में पूँजीगत माल संभित वारा अनुमोदित आवंटन का मूल्य 10 लाख डी० एन० के तुल्य रूप से प्रदिक्षित होता है [सीमानुक्रम अधिनियम, 1962 के खण्ड -15 के प्रांतीय राजस्व (सीमा-शुल्क) विभाग द्वारा अधिनियम की दर पर नियन्त्रित कर के तुल्य रूप] उसमें आवंटन के लिए प० जर्मनी के प्राधिकारियों

[कैटिएस्टाल्ट फार बोरोफ्काउ (के एफ डब्ल्यू)] की पूर्व सहमति प्राप्तयक है, और यह सहमति भारतीय भावालय द्वारा अनुबन्ध-1 के प्रपत्र में दिए गए परियोजना प्राइडों के आधार पर आधिक कार्य विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी। जब तक परियोजना जर्मनी के प्राधिकारियों से सहमति आधिक कार्य विभाग हारा लाइसेंस प्राधिकारियों (मुख्य नियन्त्रक, आयात-नियन्त्रण) को नक्ती भेज की जाती है तब तक भारतीय आयातक घो कोई भी आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है।

(2) लाइसेंस पर "1980-81" के लिए 4 करोड़ 40 लाख डी० एम० परियोजना जर्मनी पूँजीगत माल केंद्रित "अधिकार" अनिवार्य किया जाएगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लाइसेंस संदर्भ "एस/जी एन" होंगे। ये मुख्य नियन्त्रक, आयात-नियन्त्रण के आयात लाइसेंस को अधेष्ठित करने वाले पत्र में भी दुहराए जाएंगे।

(3) वैक खर्च जो सामान्य वैक पगली के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं, के प्रतिरिक्षित आयात लाइसेंस के प्रति विवेची मुद्रा के किसी घन प्रेषण की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय एजेंट का कमीशन, यदि कोई होगा, तो उसके सुगतान एजेंटों को भारत में भारतीय रूपए में जरने चाहिए, लेकिन ऐसा सुगतान लाइसेंस मूल्य का ही माय होगा और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किया जाएगा।

(4) इस आयात लाइसेंस के अधीन अधिप्राप्त किए जाने वाले माल और संबंधित सेवाएं बलिन लैण्ड या अन्य किसी देश सहित जर्मनी गणतंत्र संघ से आयात किए जा सकते हैं। इसलिए विवेची संभरक संविधान को पूर्ण करने के लिए यदि आवश्यक रूपमें तो तीसरे देश से सामान आदि अधिप्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

(5) जिस स्वतंत्र मूल्य के लिए इस केंद्रित के अधीन एक आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है वह 30,000 डी० एम० के रूप से वर्गबद्ध है (राजस्व) सीमानुक्रम विभाग द्वारा अधिसूचित मूल्य

विनिमय की दर पर गिन कर मूल्य रुपया मुद्रा विनिमय की दर, मूल्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 7४-आईटीसी (पी एन) /74, दिनांक 6 जून, 1974 के अनुमोद आयात लाइसेंस में निर्दिष्ट होनी चाहिए।

(6) लेकिन आयात लाइसेंस लागत-भीमा-भाड़ा के आधार पर 24 महीने या नीचे पैरा 2(12) में वथा निर्दिष्ट पोतावदान की अन्तिम तिथि हमें जो भी यम हो उस तक की प्रारंभिक वैधता अवधि के माध्यम से शर्त के अधीन जारी किया जाएगा कि आयात लाइसेंस की व्यूतम वैधता जारी होने की अन्तिम तिथि से 12 महीने होगी।

(7) पक्के आदेश (जिनका अर्थ है भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी सभरक को अब आदेश और विदेशी सभरक दोनों के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित कर सकिया) आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर ही अवधि निर्णीत हो जानी चाहिए। [देखिए नीचे का पैरा 1(9)], समुद्र पार संभरकों के भारतीय प्रभिकर्ताओं को आदेश और/या ऐसे भारतीय प्रभिकर्ताओं द्वारा पुष्ट आदेश स्वीकार्य नहीं है।

(8) यदि उपर्युक्त पैरा 1(7) में वथा उल्लिखित पक्के आदेश वार महीनों की समय सीमा के भीतर निर्णीत नहीं किए जा सकते हैं तो लाइसेंसधारी को आदेश देने की अवधि में बृद्धि मायते हुए एक प्रत्यावर मूल्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सं० सं० शाह० एण्ड ई०) को या अन्य लाइसेंस प्रधिकारी को जैसा भी मामला हो, इस बात का आधिकार्य और स्पष्टीकरण देते हुए प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रारंभिक वैधता अवधि के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके। आदेश देने की अवधि में बृद्धि के लिए ऐसे सावेदनों पर लाइसेंस प्रधिकारी के द्वारा गुणवत्ता ये आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक 4 महीनों की और अवधि तक बृद्धि प्रदान कर सकता है। लेकिन, यदि बृद्धि आयात लाइसेंस के जारी होने वाली तिथि से 8 महीनों में अधिक सामीं जानी है तो ऐसे प्रत्यावर लाइसेंस प्रधिकारियों द्वारा निष्पत्तम रूप से आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई०-१ अनुभाग), जिन मंत्रालय, नार्थ अंड्राक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो ऐसी बृद्धि के प्रयोक्ता मायते का गुणवत्ता के आधार पर विचार करेंगे और प्रपत्रे निर्णय को लाइसेंस प्रधिकारियों को लाइसेंसधारी की सूचना के लिए भेजेंगे। केवल लाइसेंस प्रधिकारी बृद्धि की मंजूरी प्राप्त करने वाले देने के बाद ऐसे पत्र लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत करने वाले विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत आपारी और विभागीय प्रधिकारी वैक गारंटी, संख्यात्मक स्वाप्तन करने के लिए प्राधिकारपत्र, दुख्य रूप या जमा करने की स्थीरता आदि को भुजिका फॉर्मुल्यान देंगे।

(9) लाइसेंसधारी को अपने वित्त के लिए यह सुनिश्चित करता होगा कि पक्के आदेश देने की निर्धारित अवधि के भीतर पक्के आदेश का अन्तिम रूप दे दिया जाना है। जिन मामलों में इस बात का सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, उनमें लाइसेंस प्रधिकारियों से संपर्क अरना चाहिए। विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत आपारी सम्बद्ध विभागीय प्रधिकारी इस बात का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक जांच करेंगे कि लाइसेंसधारी 4 महीनों के भीतर आदेश देने की शर्तों का पालन करता है।

(10) जिन मामलों में लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता अवधि के दोहरात लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं, उनमें लाइसेंसधारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह लाइसेंस आदेश न दिए गए ऐसे योग्य मूल्य के लिए आदेश देने से पहले उपर्युक्त पैरा 1(8) में वथा उल्लिखित तरीके से लाइसेंस प्रधिकारियों की अनुमति प्राप्त कर।

खंड 2 : कर संविदाएं निर्णीत करने मय ध्यात मे रखे जाने वाले विशेष संक्षय।

2. (1) संविदा कीमत विशेष रूप से उसी देश की मुद्रा मे अभिव्यक्त होनी चाहिए जिनमें विदेशी सभरक रहेगा है। संविदा कीमत

निश्चित और प्रत्यन्तम होनी चाहिए और किसी भी दिविश हे निया किसी भी उपबन्ध की अनुमति नहीं होती है। यदि विदेशी सभरक के किसी भारतीय एजेन्ट को ही कमीशन कुकाया जाना है तो वह भारत में भारतीय रूप से वेत सागत की मद के रूप में सविदा में इलग से प्रवर्गित किया जाना चाहिए और हवालिया विदेशी सभरक को विदेशी मुद्रा में देव कुल धनराशि भारतीय एजेन्ट के ऐसे कमीशन से प्रलग प्रवर्गित होना चाहिए। आयात लाइसेंस के आधार पर जिप मूल्य तह कर विदेश दिए जा सकते हैं, उस मूल्य की विदेशी मूल्य की विदेशी मुद्रा में गणना करने के लिए आयात लाइसेंस का मूल्य सीमा-एन्लक अधिनियम, 1962 के अण्ड-15 के प्रत्यंत राजस्व विभाग (सीमा-शुल्क) द्वारा अधिसूचित की गई प्रोर मूल्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 7४-आईटीसी (पी एन) /74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा 2 में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर पर परिकलिन किया जाता चाहिए।

(2) निजी क्षेत्र आयातकों के मामले में संभरण आदेश या तो लागत-भीमा-भाड़ा या लागत और भाड़ा आधार पर दिए जाने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामले में आदेश केवल लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए।

(3) यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आयात लाइसेंस के प्रधीन क्रय संविदाएं विदेशी सभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाव करनी चाहिए। इस संबंध में यह नोट कर लेना चाहिए कि भारतीय आयातक भारत सरकार की पूंजीगत माल समिति द्वारा अनुमोदित अनुसार प्रपत्री पसद के किसी भी देश से आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(4) प्रहृष्ट क संविदा के लिए व्यूतम मूल्य:—वर्षान्ते कि एक आयात लाइसेंस के प्रधीन क्रय संविदाएं विदेशी सभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाव करनी चाहिए। इस संबंध में यह नोट कर लेना चाहिए कि भारतीय आयातक भारत सरकार की पूंजीगत माल समिति द्वारा अनुमोदित अनुसार प्रपत्री पसद के किसी भी देश से आयात करने के लिए स्वतंत्र है।

(5)(क) आयात लाइसेंस के प्रधीन क्रय संविदाओं का भारत सरकार और बैंडिटान्सटाल्ट फर बीजोफवाऊ (के एक डब्ल्यू) परिवर्ती जर्मनी विकास बैंक जिसके मायतम से 3 करोड़ 50 लाख डी०एम० का पूंजीगत माल बैंडिट उपलब्ध किया जाता है) द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित करें। इन्हुंने एक आयात लाइसेंस के प्रधीन क्रय संविदाओं के मामले में जिनका मूल्य डी०एम० 10,00,000 के बराबर से अधिक नहीं होता तो यह नीचे की कठिका 2(13) में निर्धारित रानी के प्रधीन है।

(6) एक आयात लाइसेंस के प्रति की गई ऐसी संविदा जिनका मूल्य 10 लाख डी०एम० के बराबर रूपे या इससे कम हो (राजस्व “सीमा-शुल्क” विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर संगणित), के मामले में संविदाओं को अनुमोदन की सूचना विशेषतया आयातक को नहीं दी जाएगी। आयातक को सूचना देते हुए वित्त मंत्रालय, प्रारंभिक कार्य विभाग द्वारा के एक डब्ल्यू को एक बाबर ही संविदा दस्तावेज भेज देने पर आयातक उसी रूप में आगे कारंशाई कर भकता है जैसा कि एक डब्ल्यू द्वारा संविदा अनुमोदित कर दी गई हो और इसीलिए क्रय संविदा में इस संबंध में एक विशेष धारा मामाविष्ट करनी चाहिए।

(7) एक आयात लाइसेंस के प्रति की गई ऐसी संविदा जिनका मूल्य 10 लाख डी०एम० के बराबर रूपे या इससे कम हो (राजस्व “सीमा-शुल्क” विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर संगणित), के मामले में संविदाओं को अनुमोदन की सूचना विशेषतया आयातक को नहीं दी जाएगी। आयातक को सूचना देते हुए वित्त मंत्रालय, प्रारंभिक कार्य विभाग द्वारा के एक डब्ल्यू को एक बाबर ही संविदा दस्तावेज भेज देने पर आयातक उसी रूप में आगे कारंशाई कर भकता है जैसा कि एक डब्ल्यू द्वारा संविदा अनुमोदित कर दी गई हो और इसीलिए क्रय संविदा में इस संबंध में एक विशेष धारा मामाविष्ट करनी चाहिए।

(8) आयात लाइसेंस के प्रधीन क्रय संविदाओं का भारत सरकार और बैंडिटान्सटाल्ट फर बीजोफवाऊ (के एक डब्ल्यू) परिवर्ती जर्मनी विकास बैंक जिसके मायतम से 3 करोड़ 50 लाख डी०एम० का पूंजीगत माल बैंडिट उपलब्ध किया जाता है) द्वारा विशेष रूप से अधिकता देते हुए वित्त मंत्रालय, आवश्यक जांच करेंगे कि लाइसेंसधारी 4 महीनों के भीतर आदेश देने की शर्तों का पालन करता है।

विशेष रूप से भारतीय आयातक की भेजा जाएगा और जब तक वह ऐसा न हो तब तक संविदाएं अन्तिम समझी जानी चाहिए। इस कार्य के लिए एक प्रमाणपत्र (तीन प्रतियों में) के साथ क्य संविदा की तीन प्रतियों इस संबंध में भारतीय आयातक द्वारा विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ई०ई०सी०-१ अनुभाग) कमरा सं० ६९, नार्थ ब्लॉक को क्य संविदा के निर्णय होने की तिथि से १५ दिनों के भीतर भेजी जानी आवश्यक है कि विवेणी संभरकों से तुलनात्मक वौलियां प्राप्त करने के बाद ही आदेश दिए गए हैं।

(6) जिस मामले में संविदा लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर की गई है और विदेशी संभरक नदनुगार जहाजी बीमा प्राप्त करता है, उसमें विदेशी संभरक को स्वतंत्र रूप से परिवर्तीय मुद्रा में बीमा प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए और उसका बीमा कम्पनी से इस संबंध में एक वचनपत्र प्राप्त करना चाहिए कि यदि कोई बीमा घनराशि का भुगतान करना पड़ा तो वह सी०एम० में सीधे कें०ए०इ०इ०ल० को किया जाएगा। (उच्चार्ट बम्बम्बैंक, फैक्टर्स भेन की लेखा सं० ५०४०९१००)

(7) जिस मामले में संविदाएं लागत और बीमा भाड़ा के आधार पर की गई हैं, उसमें जहाजी बीमा किसी भारतीय बीमा कंपनी के साथ करना चाहिए और उन्नुसार बीमा किसने भारतीय उपर में चुकानी चाहिए। लेकिन आयातक को भारतीय बीमा कंपनी से निम्नलिखित वचनपत्र प्राप्त करना चाहिए और उसकी संविदा दस्तावेजों के साथ आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (ई०ई०सी०-१ अनुभाग) को भेजनी चाहिए:—

“हम किसी भी उस प्रतिस्थापन के लिए समुद्रपार संभरकों को विदेशी मुद्रा में धन, परेषण करें जिसको आवश्यकता मान की हानि या टूट-फूट के लिए हो सकती है।”

(8) चूंकि संविदाएं उपर्युक्त पैग २(२) के अनुसार या सो लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर करना आवश्यक है, इसलिए आहे भारतीय जहाज भी यहों न उपयोग किए गए हों फिर भी विदेशी मुद्रा में भाड़ा खर्च चुकाने के लिए विदेशी संभरक को उत्तरवायी बताना चाहिए। भाड़ा खर्च किसी भी परिस्थिति में भारतीय उपर में चुकाना चाहिए।

(9) लाइसेंस के प्रति विदेशी संभरकों को नीचे खंड-३ में यथा उल्लिखित विशेष सावधान के माध्यम से किए जाएंगे और इस कार्य के लिए आयात लाइसेंस के प्रति धन परेषण की किसी भी सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(10) आयात लाइसेंस के आधार पर खरीदे गए माल के परिवहन का जहाज तक संबंध है, इस विषय में क्य संविदा के अधीन माल के पोतलदान की व्यवस्था करने के लिए उन्नरकारी पर्टी ही बाह्यों को घुनते के लिए स्वतंत्र होती। पोतलदान जिस देश में संभरक बनाए गए हैं वहाँ से या हीसरे देश से किया जा सकता है।

(11) बलिन लैण्ड सहित जर्मनी गणराज संघ से खरीद के मामले में जिन संविदाओं का मूल्य १० लाख डी०एम० से अधिक है उनके लिए या अन्य देशों से खरीद के मामले में जिन संविदाओं का डी०एम० तुल्यांक १० लाख डी०एम० से अधिक है उनके लिए रोमरित किए गए माल के निपादन के संबंध में विदेशी संभरक द्वारा निपादन गारंटी को प्रस्तुत करने के लिए क्य संविदाओं में व्यवस्था होनी चाहिए। (अन्य संविदाओं के मामले में अपार्ट उग संविदाओं के लिए जिनका मूल्य उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा से कम है, भारतीय आयातक इस प्रयत्न का निपादन करने के लिए स्वतंत्र है कि उसे विदेशी संभरक से निपादन गारंटी की आवश्यकता नहीं लेकिन गारंटी निपादन का प्राप्त भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा परस्पर मन्दभूति से नय किया जा सकता है। लेकिन भारतीय आयातक को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि निपादन गारंटी से उत्पन्न यदि कोई भुगतान विदेशी संभरक से उसको देय हो से उसका

करार भैचिट टान्सटान्ट कर बीड़ोफवाक) डॉटेश वर्डेस बैंक, फैक्टर्स भैंस नेखा सं० ५०४०९१०० से सीधे किया जाना चाहिए।

(12) आयात लाइसेंस के अधीन विदेशी संभरकों को भुगतान ३१-१२-८३ को पूर्ण हो जाने चाहिए। इसनिए क्य “आदेश/विदियों में पोस्टवरनों को पूर्ण करने और ३१-१२-१९८३ तक भुगतान करने का सुनिश्चय करने के लिए उचित उपबन्ध होता चाहिए। यदि किसी मामले में वह आगा की जाती है कि भुगतान उस तिथि तक पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं तो पर्याप्त ग्रीष्मियता देने हुए आर्थिक कार्य विभाग (निपादन नेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, य००सी०प्र० बैंक विनियोग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली) से समय घुँड़ि के लिए ३१ अक्टूबर, १९८३ तक अवैदेन करना चाहिए। ऐसे आवेदनों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(13) जिन आयात लाइसेंसों का मूल्य १० लाख डी०एम० के बराबर रूपए से अधिक नहीं होता है, उनके मामले में भारतीय आयातक द्वारा क्य संविदाएं आर्थिक कार्य विभाग को एक ही बार में प्रस्तुत करना आवश्यक है। रायिदारों को खंडों वे प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उपर्युक्त पैग २(४) में विवित अहंक संविदाओं के लिए न्यूनतम मूल्य ध्यान में रखना चाहिए।

खंड-३ विदेशी संभरकों को भुगतान “विशेष” साक्षरता कियाविधि:—

(1) प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रावेदनपत्र जिस आयात लाइसेंस का कुल मूल्य १० लाख डी०एम० के बराबर रूपए से अधिक नहीं होता (राजस्व सीमा-पुल्क विभाग द्वारा अधिकृत मुद्रा विनियम की दर पर) उसके प्रति संभरकों के साथ क्य संविदाएं निर्णय हो जाने के १५ दिनों के भीतर या जिस आयात लाइसेंस का मूल्य १० लाख डी०एम० के बराबर रूपए से अधिक होता है (राजस्व “सीमा-पुल्क” विभाग द्वारा अधिकृत मुद्रा विनियम की दर पर) उसके प्रति की गई संविदाओं के कें०ए०इ०ल० के अनुमोदन की सूचना देने हुए भारत सरकार के पत्र [दिविए उपर्युक्त पैग २(५)(ग)] की तिथि से १५ दिनों के भीतर इसमें से जो भी मामला हो, उसमें लाइसेंसधारी प्रस्तुत विदेशी संभरक के पश्च में एक प्रतिरक्षितीय सामान्यता खोलने के लिए, प्राविकारान्त्र जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डॉटू ई-१ अनुभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली की निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:—

(क) जिन मामलों लाइसेंसों का मूल्य १० लाख डी०एम० के मूल्य रूपए से अधिक नहीं होता उनके लिए की गई संविदाओं के संबंध में:—

(1) क्य आदेश की तीन प्रतियां, और विदेशी संभरकों द्वारा क्य आदेश के पुष्टिकरण की तीन प्रतियां जो क्रमशः आयातक एवं संभरक द्वारा विनियोग इस्तान्तरेन हों या उनकी फोटो प्रतियां साश्वर्तीकृत प्रतियां या भारतीय अधिकृताओं को दिए गए आदेश और ऐसे अधिकृताओं द्वारा की गई पुष्टि स्वीकार्य नहीं हैं।

या

क्य संविदा की तीन प्रतियां भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विनियन हस्ताधरित या उनकी फोटो प्रतियां साश्वर्तीकृत प्रतियां या भारतीय अधिकृताओं को दिए गए आदेश और ऐसे अधिकृताओं द्वारा की गई पुष्टि स्वीकार्य हैं।

(2) अनुबन्ध-२ में निर्धारित प्रथम में प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए आवेदन (वो प्रतियों में)।

(3) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले प्रतिकृत एक भारतीय आयातक द्वारा प्रस्तुत भारतीय आयातकों के मामले में लागू नहीं।

(4) लागत और भाड़ा संविदा के मामले में भारतीय घीमा कंपनी के बबतपत्र की तीन प्रतियों देखिए उपर्युक्त पैरा 2 (7)।

(5) इस संबंध में तीन प्रतियों में प्रमाणपत्र कि विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाबत आदेश दिए गए हैं, ऐसिए उपर्युक्त पैरा 2 (3) और

(6) इस संबंध में एक प्रमाणपत्र कि लाइसेंस के अधीन आगे कोई भी संविदा नहीं की जाएगी, ऐसिए उपर्युक्त पैरा 2/(13)।

(७) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य 10 लाख रुपये के तुल्य रूपए से अधिक होता है उसमें प्रति दी गई संविदाओं के संबंध में।

पहले भेजे गए संविदा दस्तावेजों (जिनमें संबंध में के ०१फ० उच्चमू० का अनुमोदन वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, द्वारा प्राप्त किया जाएगा [देखिए उपर्युक्त पैरा 2 (5) (ग)], के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:—

(1) अनुबंध-2 भी निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए एक आवेदनपत्र (दो प्रतियों में)

(2) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत एक भारतीय बैंक से अनुबंध-3 के रूप में निर्याएँ प्रपत्र में एक बैंक गारंटी (सार्वजनिक बोत के आपातकों के मामले में लागू नहीं) और

(3) लागत और भाड़ा संविदा के मामले में भारतीय घीमा कंपनी के बबतपत्र की तीन प्रतियों देखिए उपर्युक्त पैरा 2 (7)

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक बोत के आपातकों के मामले में किसी भी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

(3) साखपत्र खोलना

साखपत्र इस प्रयोजन के लिए परिवर्त्तन के निम्नलिखित नियमों के अनुसार भौतिकों में से किसी एक बैंक में प्राधिकार पत्र के बल पर खोला जा सकता है:—

(1) दि बेयरिये बेरिन्स बैंक, मधुनिख

(2) दि कार्मस बैंक ए० जी० फैकफट

(3) दि ल्यूट्रो बैंक, ए० जॉ०, हेम्बर्ग

(4) दि फ्रेस्टनर बैंक, ए०जी०, जंगर्फनस्टी, हेम्बर्ग

(5) ब्लिनर ट्रेस्डिस गेगलगोप्ट, फैकफट बैंक

(6) स्टेट बैंक आफ इंडिया, फैकफट

(7) ब्रिटिश एंड बेस्ट बैंक, हेम्बर्ग

(8) बैंक फर जेमियन्स रिटम-क्राफ्ट (बी एफ जी)

आपातकों (सार्वजनिक बोत और निजी बोत दोनों के), और उनके बैंकों को उपर्युक्त पैरा-3 (3) में उल्लिखित वाठ बैंकों में से उनके द्वारा चुने गए जर्मनी के बैंक को विशेष रूप से नियिष्ट करना चाहिए।

(4) (क) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य 10 लाख रुपये के बाबत आवश्यक है उसके प्रति आदेशों के मामले में एक आदेश देने की तिथि से या

(ख) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य 10 लाख रुपये के बाबत रूपए से अधिक है उसके प्रति संविदा के मामले में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संविदा के प्रमुखोंन के पत्रों की नियि से अलग हनमें जो भी मामला हो उसमें 15 दिनों के भोतर प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए आवेदन करने में असफल रहने पर आयात विवरण वित्तियों का उल्लंघन समझा जाए।

3 (5) बैंक गारंटी—यह अनराशि जिसके लिए यह निष्पावित करनी चाहिए।

जहां कहीं प्राथमिक हो, बैंक गारंटी जिस घानराशि के लिए विदेशी मुद्रा/साखपत्रों मांगा गया है उसके तुल्य रूपए के ब्योतक घनराशि के लिए प्रासंगिक तथा बननवढ़ता बैंकों और इसमें अतिरिक्त व्याज तथा अनुबंध 5 में यथा उल्लिखित अन्य बैंकों के लिए इस घनराशि के 1% के लिए होती चाहिए। परिवर्तन की प्रचलित दर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खंड-15 के अन्तर्गत राजस्व (गोमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचना मुद्रा विनियम की दर और नार्वेंजनिक सूचना सं 78-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 8-6-1974 के पैरा 2 के अनुसार आपात लाइसेंस में नियिष्ट दर होती इस दरका तात्पर्य केवल आयातक द्वारा भेजी जाने वाली बैंक गारंटी का मूल्य निकालने के लिए है। लाइसेंस के अधीन किए गए आयातों की विदेशी मुद्रा लागत के प्रति सरकारी लेवल में इयमा विनियोग करने के लिए तुल्य रूपए की गणना विदेशी संभरक का मुगातात करने की व्यवस्था करते समय जसनं बैंक द्वारा खंड की गई छी० एम० धनराशि के लिए मिलित दर पर करनी होती अधीत या तो भी एम में यदि विदेशी संभरक परिवर्ती (बैंकन लैंड चहिया) में रहता है या अन्य नाम्य पर दवा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं 15-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 28-1-1972, सार्वजनिक सूचना सं 108-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 21-7-72 और 8-आईटी सी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 के अनुसार किसी अन्य देश जिसमें विदेशी संभरक रहता है, की मुद्रा में भुगतान को प्रभावी करने के लिए छी० एम अनुबंध-5 में आगे नोटिस जारी होने तक इस संबंध में जड़ और जैसे हो कोई परिवर्तन आवश्यक होता आधिकृति कर दिया जाएगा।

(6) प्राधिकार पत्र जारी करना:

यदि उपर्युक्त पैरा 3 (1) में नियिष्ट दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो परिवर्त जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक में आयातक का भारतीय बैंक द्वारा खाले जाने वाले “विशेष” साखपत्र के प्राधार पर विदेशी संभरकों की निर्धारित घनराशि तक मुगातात करने के लिए प्राधिकृत आयातक का भारतीय बैंक द्वारा खाले जाने वाले परीक्षा नियमक) आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ए० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, परिवर्त जर्मनी में नामित वाणिज्यक की एक प्राधिकारपत्र (अनुबंध-4 के अनुसार) जारी करेगा। ऐसे प्राधिकारपत्र की एक प्रति भारतीय लाइसेंसधारी को भेजा जाएगी। मूल प्राधिकारपत्र उसी एक प्राप्त के साथ साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत सम्बद्ध भारतीय बैंक को इसके द्वारा खाले गए साखपत्र के साथ मूल प्राधिकार का परिवर्त जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक को भेजने के लिए आदेश देते हुए भेजा जाएगा। (ऐसा निर्देशन अनुबंध-5 के अनुसार होगा) इसका एक प्रति भारतीय का भा भेजो जाएगी।

जब तक इस परे में यथा उल्लिखित प्राधिकारपत्र भारतीय बैंक ने सहायता देखा तथा लेखा परीक्षा नियमक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से सीधे प्राप्त कर लिया हो तब तक भारत के किसी भी बैंक को साखपत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंसधारी को सुविधाएं प्रदान नहीं करपी चाहिए।

(7) परिवर्त जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक में “विशेष” साखपत्र प्राधिकारपत्र जारी होनी की तिथि से 30 दिनों के भीतर सहायता देखा परीक्षा नियमक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ए० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते हुए खोला जाता जाहिए। अवश्य पहले ही जारी किया गया प्राधिकारपत्र बैंक नहीं समझा जाएगा।

3(8) अवेक्षित दस्तावेजों और विवरणपत्रों को एकत्र करने पर परिवर्त जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक द्वारा विदेशी संभरकों को मुगातात किया जायेगा। जिस मामले में विदेशी संभरक जर्मनी गणतंत्र संघ (बैंकिन लैंड सहित) से अन्य देश में रहता है उसमें भी समझोती की बात चीत और दस्तावेज का भुगतान परिवर्त जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक द्वारा किए

आएंगे। पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्य थैक पश्चिमी जर्मनी प्राधिकारियों से द्वीप एम धनराशि की अवायगी प्राप्त हो रही। जर्मनी गणपति संघ से अस्थ देशों द्वारा संभरण के मामले में पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक थैक विवेशी संस्करणों को जिस देश में वे रहते हैं उन्हें देश की मद्दा में भुगतान करने के लिए अपने द्वारा खर्च की गई धनराशि की अवायगी द्वीप एम जर्मनी के प्राधिकारियों से प्राप्त हो रही।

3 (9) जर्मनी गणतंत्र संघ में मुगातान के लिए घोर तोसरे देश में मुगातान की व्यवस्था करने के लिए भी जर्मनी के बैंक द्वारा किए गए भारुचिक बैंक खर्चों जिस यामले में भी दायू होंगे, वे भारत के सम्बद्ध बैंक द्वारा जर्मन बैंक को साधारण बैंक प्रणाली से भारत भरकार के लेखे को प्रभावित किए दिना प्रेषित किए जाएंगे।

पार्ट-4 सरकार के लेखों में उपर्युक्त अस्त करने के लिए उत्तरदायित्व

4(1) वर्लिन लींड सहित पश्चिमी जर्मनी में और ब्रिटेन में ग्राम्य दैवतों ने ग्राम्यता के दोनों में पश्चिम जर्मनी के नामित वाणिज्य बैंक हार्टा मूल लदान दस्तावेज भारत में सम्बद्ध थीं को भेजते चाहिए, जो दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर इन परकारात्मा दस्तावेजों के लिए को लाइसेंसिशनी को केवल इस बात का सुनिश्चय करने के बाद देगा कि पश्चिम जर्मनी नामित वाणिज्य बैंक द्वारा जर्मनी के संभरकों को चुनाई गई हो। ऐसे धनराशि के ब्राबंडर रूपया या जर्मनी के सम्बद्ध थीं द्वारा ही सरें देगा में संभरक को भुगतान करने की व्यवस्था करने में अच्छी की गई हो। ऐसे धनराशि और इसका 1 प्रतिशत आर्युपंगिका का और बचनबद्दता खर्चों के लिए और विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि ने सरकार के लिए में सुल्य रूपया जमा करने की तिथि तक (दोनों दिन मिला कर) की अधिकि के लिए उपर्युक्त कूल धनराशि व्याज खर्चों आयातक से प्राप्त कर लिए जाते हैं और सरकारी लेखों में जमा किए गए हैं। सार्वजनिक मुक्तना सं. 46-भार्डोटी १० सी० (पी० एन०) / ७६, विलांक १६ जून, १९७६ के भनुसार व्याज खर्चों की गणना विस्तृतिवित अनुसार को जाएगी, १५ जून, १९७६ को या ऐसके बाद सरकारी लेख में जमा करने की बात:-

(1) जहां सर्वेक्षक को मुगतान की तिथि से 30 दिनों 9% प्रति वर्ष के भीतर निम्नों किए जाते हैं

(2) जहाँ संभरक को भूगतान की तिथि से 30 दिनों के बाद निक्षेप किए जाते हैं

| | |
|----------------------------------|----------------|
| (क) पहले 30 दिनों के लिए | 9% प्रति वर्ष |
| (ख) 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए | 15% प्रति वर्ष |

विवेकी संभरकां को विदेशी मुद्रा के तुल्य रूपये में किए गए भुगतान की गणना के लिए अपनाई जाने वाली विनियम दर मुख्य नियंत्रक, आयात-नियर्ति की सार्वजनिक सूचना सं० ४-झाई०ट००सी० (पी०एन) /७६, दिनांक १७-१-७६ में यथा निर्धारित भिली-जूनी दर होनी या दमय-नस्मय पर मुख्य नियंत्रक आयात-नियर्ति की सार्वजनिक सूचनामौर्छे के माध्यम से या रिक्वेट ऐक आफ हिन्द्या के विनियम नियंत्रण परिवर्तों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली दर हो सकती है। भारतीय सम्बद्ध दैक की यह जिम्मेदारी होनी कि आयातकों को मुल प्रोत्तशब्दान वस्तावेजों के सौनपने से पूर्व मह मुनिष्यक्य कराए कि देय धनराशि ठीक प्रकार सरकारी लेदे में जमा करा दी गई है। लाइसेंसधारी को यह भी मुनिष्यक्य करना आहिए कि उतने दैकरों से वस्तावेजों को लेने से पूर्व सरकारी लेदे में देय धनराशि ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है।

(2) उपर्युक्त 4(1) में विचार किए गए निम्नों की धनराशि या तो रिजर्व बैंक भाक इंडिया, नई विल्सी एस स्टेट बैंक भाक इंडिया, तीक्ष्ण दृष्टारी, विल्सी-6 के नाम डिमार्ड ड्राफ्ट के माध्यम से मार्शलिक गृहनामा सं। 74- मार्ई-टी०सो० (पी०ए०न०)/74, दिनांक 31 मई, 1974 घोर सार्वजनिक सुचना सं। 132 मार्ई-टी०सो० (पी०ए०न०)/71 दिनांक 5 अक्टूबर,

1971 द्वारा यथा संशोधित सर्वजनिक सूचना सं. 233-प्रदृष्टी०१०००० (पी०एन०)।३८, दिनांक २४ अक्टूबर १९६४ के अनुसार, अधिकारी सेवे में जमा करने के लिए प्रेषित की जा सकती है। धनरात्री या नहरों के लिए लेखा शोधक “कृष्णोजिट्स एंड एक्षेमिस—कृ.” डिपोजिट्स भोट विधिरा हट्टेस्ट ४४३—सिकिन डिपोजिट्स डिपोजिट्स फार परवेजिज एक्सेस्ट्रा एक्सेस्ट इयरेक्ट पेसेन्ट ग्रोसीजर डिपोजिट्स फार कोस्ट बाफ वाणीज एंड एक्स्प्रेसेंट आर्टैक्ट एंडर वि वेस्ट जर्मन कॉपिटल ग्रुप ड्रैटिट फार १९७८-७९ (ही एम ३ करोड़ ५० लाख) ” है।

(3) भनपरेषण सांबंधित मुच्चासंख्या सं० 74-माई०टी०१०३०(पी०एन)/
74, दिनांक 31-5-74 में निर्धारित किए गए खालील प्रपञ्च द्वारा जारी
किए जाएँगे।

(4) रिंजन बैंक नाफ हड्डिया, मई दिल्ली था स्टेट बैंक आफ्रा हड्डिया, दीप हजारी, दिल्ली ६ में चालान की पाक प्रति या स्टेट बैंक आफ्रा हड्डिया, तीस हजारी, दिल्ली-६ को छिमांड इफट प्रस्तुत करने के संबंध में सूचना, जिस भारतीय बैंक ने गरिमों जारी की है उसके द्वारा सहायता लेखा तथा लेया परीक्षा नियंत्रक प्रार्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक विल्हेम, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को यशवन्त जर्जन के नामित बैंक से प्राप्त की गई सूचना टिप्पणियों का उर्जा द्वारा दी गई प्रतीक्षण पत्र के साथ भेजी जाएगी।

(5) बोंबल प्राविधिक व्यापारियों के माध्यम से अरेक्षित रखा जामा करने और सार्वजनिक सूचवा सं० 184 पाई० टो० सौ० (री० एन०/68 दिनांक 30 अगस्त, 1968 के यनुसार उम्ही से लाइसेंस की मुद्रा विनियम तिव्रतंत्र प्रति भा० पृष्ठाकृत कराना आवायतीं के विशेष विनियार्थ होता। उन्हें रिट्जिं वैकू पाक इंडिया द्वारा यथा विधिवत अरेक्षित "एस" प्रवक्ष भी भरना चाहिए।

(6) एक लाइसेंस के अवैत आयात पूर्ण कर देने के बाद और विशेष सभी धनराशि आवश्यकों/बैंकों द्वारा [लेखे में जमा कर देने पर प्राप्त किए गए] आयात साल प्लॉइर जमा किए। गए रुपए के ब्वारे सकृदायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियमक, विस संन्तालय, भार्थिक कार्य विभाग पूर्ण सी० प्लॉइर बैंक बिल्डिंग, पालियामेट स्ट्रीट, तहसीली को मनुष्यध-८ में यथा-निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने चाहिए। जिससे कि वित्त संन्तालय उनका सत्यापन करके, जहां आवश्यक हो, आयातकों द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी को रिहा करने के लिए अवस्था कर सके।

अम-5 संखिया से परिष्कर्ता

संविदाओं की माल की सूची थी, या भुगतान की अनुमति, माल के मूल्य आदि से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए वित्त मंत्रालय और के० एफ० डब्ल्यू० प्राप्तिकरियों का अनुमोदन प्राप्त करना प्रायः यह कहाँगा, इसके परिणामत्वकै चाहे भुगतान पहले करना पड़े या उसका स्थगित करना पड़े। अत्यतर्कों द्वारा उपर्युक्त परा 2(5) में यथा उल्लिखित तरीके से भारत सरकारकि० एफ० डब्ल्यू० के अनुमोदन के लिए कार्यवार्षीकै ऐसे परिवर्तन की सूचना ग्राहिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय नई दिल्ली (एस०ह०१ सी०१-१ अनभाग), नाथ॑ ब्लाक को उपल्लेख देनी चाहिए।

ખંડ-૬ રિટોર્ડ ભેન્ચ

शोदेगा देने, माल की सुपुर्दी, विवेशी संभवतों को भूगतान वादि को प्रदर्शित करते हुए लाइसेंस के जारी होने की सिथि से प्रारम्भ करके अनुबंध-7 के अनुसार एक दैनासिक रिपोर्ट दो प्रतियों में वित मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (६०५०३०-१ अनुभाग) कमरा नं० ६९, नार्थ अंडा०, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए और इसको भेजना तब तक जारी रखना चहिए जब तक हि संविदा के अवीन सभी पोलिक्षण और सभी भूगतान दूर्ण न कर निए जाएं। इस नाम डॉ०६०० के तुल्य धरमे (एजेस्टी सीमा शुल्क विभाग डारा अधिकृति यमा विजिन की दर पर) से

प्राधिक के आवंटन के मामले में उपर उल्लिखित वै-गोत्रिक रिपोर्ट के प्रति-रियत प्रत्येक अध्यक्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को अनुबन्ध-8 में निर्धारित प्रपत्र में एक अधिकारिक रिपोर्ट (वो प्रतिवेदी में) भी यदि कोई विशेष घटना हो तो उस पर परियोजना की प्रगति पर और परियोजना को पूर्ण करने के लिए समय-समय अनुसूची के पालन पर प्रस्तुत करनी चाहिए और इसके साथ आय करने वाली भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (वो प्रतिवेदी में) भी जब तक परियोजना पूर्ण नहीं हो जाती कम से कम सीन वर्षों तक भेजना आवश्यक होगा।

खंड-7 विधि शर्तें

(1) लाइसेंसधारी को आमत नाइटेंस में किसी भी ऐसी शर्त संभरक को अवधारणा करना चाहिए जो लेन-देन का अनुपालन करने में संभरकों को प्रभावित करें।

(2) विवादः—यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय आयतक और विदेशी संभरक के बीच यदि कोई भी विवाद उठेगा तो भारत सरकार उसके लिए कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेगा।

(3) अनुदेशों का पालन—आमत लाइसेंस ने संबंधित उसके कारण उठने वाले किसी एक या सभी मामलों के संबंध में के एक डब्ल्यू प्राधिकारियों के साथ 4 करोड़ 40 लाख डी० एम० के पूंजी गत माल समझौते के अधीन सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए भारत सरकार हारा समय-समय पर जारी किए गए फिरी भी नियंत्रण, प्रनुवेण और आवेदन का लाइसेंसधारी को नुग्न यापन करना होगा।

(4) अतिक्रमण या उल्लंघन—उपर्युक्त धाराओं में निर्धारित शर्तों का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर प्रायान तथा नियंत्रण (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कायंकाई वी जाएगी।

(5) अनुबंधों की अनुसूची—

अनुबंध—1 परियोजना आंकड़ों का प्रपत्र

अनुबंध—2 प्राधिकारी पत्र की जारी करने के लिए आवेदन का प्रपत्र

अनुबंध—3 बैंक गारंटी का प्रपत्र

अनुबंध—4 प्राधिकारी पत्र का प्रपत्र

अनुबंध—5 प्राधिकारपत्र को भेजने के लिए अनुदेशों का पत्र

अनुबंध—6 बैंक गारंटी की रिहाई के लिए इकाया निष्कोपें की रिपोर्ट व आवेदन पत्र का प्रपत्र

अनुबंध—7 वैमासिक रिपोर्ट प्रायुत करने के लिए प्रपत्र

अनुबंध—8 अधिकारिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र 1 लाख रुपए से अधिक के मामले के लिए नाहू है।

अनुबंध 1

परियोजना आंकड़ा प्रपत्र

केफिटस्ट्रास्ट फर वाइटोपो

6. केन्ट-फर्ट मेन, जारी अंकीय गणराज्य पायान-ग्रिमेन्सी -०

अमेन पूंजीगत माल क्रह से विदेशी मुद्रा के लिए

आवेदन पत्र

परियोजना आंकड़ा

(1) आवेदक (फर्ने)

(क) पंजीकृत कार्यालय (राज्य सहित पता)

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र या नियंत्री क्षेत्र संस्थान

(ग) आवार नाइट/उद्योग की जारी

(घ) कंपनी के भागीदार

(ङ) विदेशी सहयोग समझौता

(2) अर्थात् किए जाने वाले पूंजीगत माल की किस्म

(3) पूंजीगत माल के चुनाव नाइटर—हाया प्रपत्रही गई प्राप्ति कियाविति का संकेत करें। पूंजीगत माल ज्ञान किसी भी देश से बरीद के लिए उपलब्ध है इसलिए इस संबंध में संकेत किया जाए। चाहिए प्राप्ति कियाविति देशों में निवार पूछताछ की गई चालू की गई थी और वह प्राप्ति क्या है जिसके लिए विशेष संभरक का चुनाव किया गया है।

(4) संभरक (नाम और पता)

(5) संपूर्ण परियोजना का संक्षिप्त विवरण (जिसके लिए ऐसे पूंजीगत माल भी आवश्यकता है)

(6) निम्नलिखित मांकों के विश्लेषण के साथ संपूर्ण परियोजना की स्थानीय और विदेशी मुद्रा में कीमतः—

—भूमि एवं भवन

—मालीमरी एवं उपकरण

—परिचालन विधि

—विविध

(7) संपूर्ण परियोजना के लिए स्थानीय एवं विदेशी वित्तीय स्रोतों (वित्तदान) के माध्यमों से संबंधित मालिक विवरण। इस बात की विट्ट कर लेना चाहिए कि अप्यार्थ—वित्तदान मुरक्किल है और इस आवेदन पत्र के अंतर्गत न ग्राने वाली विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएँ तुरा कर सो जाती हैं।

(8) प्रत्येक गए श्रोतोंका लाइसेंस के लिए उद्देश्य पत्र

(9) मंत्रजनकद एवं नाम तथा दृष्टि लेखे के साथ पत्र दो वर्षों का वार्षिक रिपोर्ट। यदि उपलब्ध हो तो मकानी—गति एवं लाभ का पूर्वानुमान।

(10) कमता

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्तमान कमता का श्रौतस उपयोग

(ख) उपयोगीन के मामले में शुप्ता मुक्त फारण हैं।

(11) विनियान किए जाने वाले उत्पादों की मार्किट स्थिति (यदि संभव हो) तो भूत एवं सम्भावी विकास के आंकड़ों को प्रदर्शित करें।

(12) रोजगारः—

(क) कर्मचारियों की वर्तमान संख्या

(ख) परियोजना पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त कर्मचारी

(13) कारबेगाल के संभरण स्रोत

(14) परियोजना के निष्पादन के लिए समय-सारिणी

अनुबंध 2

प्रधिकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय,

प्राधिक कार्यालय,

यूसी०ओ० बैंक बिलिंग, परियोजना मूल्यांकन,

महि दिली।

विषयः—1980-81 (जी०एम० 4 करोड़ 40 लाख) के लिए परियोजना पूंजीगत माल केंद्रित के अंतर्गत गति एवं लाभ का आवाहन।

गणराज्य,

ऊपर उल्लिखित परियोजना जमीनी पूंजीगत माल केंद्रित के अंतर्गत से का आवाहन के संबंध में

हृषि निमनलीलिंग और आपको देते हैं ताकि आप...
के माध्यम से वेरेस्से बैरेस म्युनिशन अधिकार कार्पेज बैंक ए जी फैकफेट
अधिकारी हृषि लैन बैंक ए० वे० हृषि अधिकारी ट्रैसेनर बैंक ए जी जंगपरस्टीट,
हृषि अधिकारी ट्रैकस्टर बैंक फैकफेट ए एम डेन या स्टेट बैंक आफ हृषिया
फैकफेट या वेरेस्से एंड बैस्ट बैंक हृषि में अधिकारी बैंक फार जी मिम-
वर्टसचैन (बी०एम०जी०) में साखात्र छोलने के लिए प्राधिकार पद जारी
कर सके।

(क) आयातक का नाम और पता

- (1) क्या सार्वजनिक बैंक का है या निजी सेक्षंस संस्थान का
- (2) उचित की श्रेणी किससे वह संबंध रखता है।
- (3) वह राज्य जिसमें स्थित है।

(ख) लाइसेंस की संख्या दिनांक एवं मूल्य (लाइसेंस की ओटो) प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

(ग) भुगतान नियमों अर्थात् (आगत बीमा भुगता या आगत भाड़ा) किसी भी मामलों में केवल जटाज पर्वत नियुक्त मूल्य के लिए प्राधिकार पद के लिए आवेदन नहीं किया जाना चाहिए को इसकी हुए संभरक द्वारा दिए गए और स्वीकार किए गए आवेदों का विवेशी मुद्रा में मूल्य।

(घ) इस संबंध में एक प्रमाण पत्र कि पक्षे आवेदा (संभरक के पुष्टिकरण आवेदन के साथ) आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से आगे मास के भीतर दिए गए हैं। यदि 4 मास की नियांसित अवधि के बाद आवेदा दिए गए हैं तो जैसा भी भासला हो मुख्य नियंत्रक आयात-नियति को पत्र/कित्त मंत्रालय के पक्ष की एक प्रति जिसमें आवेदा देने के लिए समय दिया दिए गए प्राधिकार दिया गया है, संलग्न की जानी चाहिए।

(इ) इस संबंध में तीन प्रतियों में एक प्रमाण पत्र कि दमुंड-पार संभरकों से तुलनात्मक बोलियाँ प्राप्त करने के बाद पक्षे आवेदा दिए गए हैं और वह कि भूगतान उपयुक्त जर्मनी की द्वारा स्वीकार कर दिए गए हैं। यदि तुलनात्मक बोली प्राप्त करना संभव नहीं है जैसा एक प्राधिकार मह. तो इसके लिए पूरे भौतिक दिए जाने चाहिए।

(झ) आयात किए जाने वाले मान का संक्षिप्त विवरण।

(ঞ) वास्तविक विवेशी मुद्रा में वह घनराशि (उस देश की मुद्रा में व्यक्त किया जाना है जिसमें संभरक रहता है) जिस लिए प्राधिकार पद की मांग की गई है अनुकरण के कमीशन को छोड़कर।

(ঞ) विवेशी मुद्रा में अनुकरण की घनराशि और भारतीय अनिकता का नाम और पता।

(ঞ) ऐसे मामले में जहाँ संभरक प्रशिक्षण जर्मनी से भिन्न देशों में स्थित हैं, तो संभरक के लिए उस बैंक का नाम दिया जाना चाहिए जिसमें बैस्ट जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा घनराशि प्रेषित की जाती है।

(ঞ) सुषुद्दी पूर्ण करने की अनुमतिशीलता।

(ঞ) संभिता अन्तर्गत भुगतान के लिए पक्षे वाली सम्भावित तिथि को प्रदर्शित करने वाली एक अनुसूची।

(ঞ) 1 मिलियन बी० एम० के० बराबर आयात लाइसेंस के मूल्य के मामले में यह असारे हुए एक प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए कि आयात लाइसेंस के महे सभी संविदाएँ पूरी कर

दी गई हैं और आगे कोई भी संविदा नहीं की जाएगी जिसके द्वारा आयात खोला जाएगा।

(विवेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकूल भारतीय अनुभवित बैंक का नाम और पता) और उपर उल्लिखित बैंक द्वारा ८० के लिए वी गई बैंक गारंटी संख्या दिनांक और जो स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की द्वारा ३१ के अनुसार स्टाम्प कार्ड द्वारा दिया गया नियम नियमित की गई है। संलग्न है।

प्रबोध,

(लाइसेंसधारी)

प्रति बैंक को सुचनार्थ प्रेषित।

अनुबन्ध—३

गारंटी बैंक

संवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के लिए (इसके बाद इसे "सरकार" कहा गया) प्रशिक्षण जर्मनी पूँजीगत भाल ऑफिट १९८०-८१ की शर्तों के अनुसार तथा कार उल्लिखित करार के महे आयातक के नाम में आयात के अनुसरण में दिनांक को जारी किया गया लाइसेंस संख्या का दालन करने हुए के हाथ बाद में इसे "आयातक" कहा गया है) के आयात के लिए भुगतान के लिए राजी होने हुए (विवेशी मुद्रा में उपयुक्त घनराशि का संकेत करे) आयात के अनुराध पर हम आयातक द्वारा भनीत (बैस्ट जर्मनी में वाणिज्यिक बैंक का नाम) बैंक द्वारा भुगतान की गई घनराशि को जाने करने के लिए परिवर्तन का चालू परिवर्तन दर पर जो इस संबंध में समय समय पर मरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों वे अनुसार परिवर्तित किया जाता है और इसके साथ १ प्रतिशत की विवेशी संभरक को किए गए भुगतान को तारीख को संस्कारी लेख में कोइट के लिए समयमुद्धय कृपय के भुगतान की तारीख तक प्रथम ३० दिनों के लिए ९% वार्षिक दर से और इसके अधिक का अवधि के लिए १५% वार्षिक दर के हिसाब से व्याज के साथ भुगतान के परामर्श की पावनी की प्राप्ति के बाद दिनों के भोतर विधि के साथ भाल सरकार के कैटिट के लिए और उक कैटिट के अन्वयन उपनुक लेख शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा लेखा गया के महे संकेतित है, अवध्या करने का बार लेते हैं। बैस्ट जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्राप्त आयातक प्रमेलों का परकार्य दें आयातक को केवल तभी लोडाया जाएगा जष्ठिं कर ये प्रोक्रिशन पूरे रखें जाना कर लाएं गए हैं।

2. हम, वि बैंक सरकार जहाँ और जैसा भी, समय समय पर निवेश वे, आयातक द्वारा समय समय पर सरकार को दी जाने वाली किसी भी प्रकार को राशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य हो या उपका कोई भी अंश जो आयातक द्वारा योड़े समय के लिए बचाया भीर दें रह गया है, जिसमें विवेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से इस पर प्रथम तीन दिनों के लिए ९% वार्षिक दर और इनसे अधिक अवधि के लिए १५% वार्षिक दर के हिसाब से व्याज भी शामिल है, ऐसी राशि जो ८० से अधिक नहीं है, आयातकों द्वारा भासान करने में वेर होती, तो उसकी भी अंति से सरकार को दूर रखेंगे और उसकी अलिंगित करेंगे। आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की वेर होने पर अथवा उसकी भीर से भीर सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के मंबंध में जो राशि हमारे

अनुच्छेद - 5

विषय— 1980-81 के लिए डी०एम० 4 करोड़ 40 लाख परिचम जर्मनी पूर्जीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत आयान, साक्षपत्र खोलने के विषय प्राधिकार पक्का जारी करना।

प्रिय महाराज,

..... मे पक्का संख्या दिनांक के सबर्थ मे, जिसमे उन्होने 1980-81 के लिए डी०एम० 4 करोड़ 40 लाख परिचम जर्मनी पूर्जीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत आयान के बैंक द्वारा साक्षपत्र खोलने की अनुमति मार्गी है, मे उन्हे विदेशी संभरक को तक भुगतान की व्यवस्था के लिए प्राधिकृत करने हुए प्रायिक कार्य विभाग की पक्का स०
दिनांक संलग्न करता है इस (एक अतिरिक्त प्रति के साथ)
प्राधिकार पक्का आपके द्वारा खोले गए साक्षपत्र के साथ
को भेज दिया जाना चाहिए।

2 इस विभाग को अवगत करने हुए इस पक्का के जारी होने की तारीख के तीस दिनों के भीतर आपको साक्षपत्र खोलने का प्रधिकार दिया जाना है जो इसकी धनराशि से प्रधिक नहीं होनी चाहिए। विनियम नियंत्रण नियम पुस्तक के भाग-७ की कड़िका 10 के अनुसार यह सुनिश्चित कर देना अपेक्षित है कि पोस्टलदाता की अन्तिम तारीख निश्चित होने के बाद साक्षपत्र की समाप्ति की तारीख 45 दिनों से पहले नहीं है और कि संवधित आयान साक्षेम मे बनाया गया है या प्राधिकारपत्र मे जो तारीख वी गई है उनमे से चाहे जो भी पहले हो वही होनी चाहिए। साक्षपत्र खोलने से पूर्व, आयानक इस बान के लिए कृपया सुनिश्चित हो जाएं कि उसके पास वैध आयान लाइसेंस है।

3. आपसे अनुरोध किया जाता है कि से दस्तावेजो की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर ही आपके द्वारा को गई मर्यादा के अनुमार आप सेण्ड अनिन गहित जर्मन मंथीय गणराज्य मे संभरक के लिए डी०एम० मे भुगतान को १% अन्य देशों के विदेशी संभरको के लिए अन्य विदेशी मुदा मे भुगतान की ओर इनके साथ एक प्रांतशत के हिसाब से अनुवर्तिक और सौदे प्रभागों को प्रभावी बनाने के लिए

(परिचयी जर्मनी मे नामित विधिय वैक का नाम) जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरको को चुकाई गई धनराशि के समतुल्य रूपये द्वारा इसें आर्क मे वर्च की गई धनराशि के समतुल्य रूपये की गणता अगली सूचना के जारी होने तक सार्वजनिक सूचना स० १५--आई टी सी (पी एन)/७२, दिनांक २८-१-७२ एवं सार्वजनिक सूचना स० १०८-आई टी सी (पी एन)/७२, दिनांक २१-७-७२ और ८--आई टी सी (पी एन)/७६ दिनांक १७-१-७६ मे द्या सकेतित अद्वितीय दरों को मिनी जुली दर से परिशित की जाएगी। जब कभी विनियम की आई एम ०५ की सम दर मे परिवर्तन होता है तो जो दर मंथोधनादीन है संभरक को भुगतान की तिथि से और जिस तिथि को समतुल्य रूपया जमा किया गया है (दोनों बिन मिला कर) प्रथम तीस दिना है तो ५% वापिक दर से और इससे प्राधिक के लिए १५% वापिक दर के हिसाब से व्याज भी सरकारी नेत्रों मे जमा करता है। आयानक को आयान प्रलेखों का दिए जाने से पूर्व इन धनराशियों को जमा करने की व्यवस्था करता आपकी जिम्मेदारी होती।

4 ये धनराशि या तो रिजर्व बैंक आफ ईरिया, नई दिल्ली या स्ट्रट बैंक आफ ईरिया, तीस हजारी, किली-६ मे जमा वी जाने चाहिए या स्ट्रेट बैंक आफ ईरिया की किसी आप्ता या इसके नियक्ता (आवेदक) के द्वारा आपको प्राप्त डिमांड ड्रेफ्ट जो स्ट्रेट बैंक आफ ईरिया, तीस ९३३ ८१,८०-२

हाँगी, शिली ६ (आवेदिता शीर पाने वाला) के तामे नियानी और भुगतान के लिए है, उसके द्वारा जमा की जर्नी चाहिए। इस संबन्ध मे आपका जान सार्वजनिक सूचना स० ७४--आई टी सी (पी एन)/७४, दिनांक ३१-५-७४ द्वारा यथा संसार्धित सार्वजनिक सूचना स० २३३--आई टी सी (पी एन)/६४, दिनांक २४ अक्टूबर, १९६३ एवं संख्या १३२--आई टी सी (पी एन)/७१, दिनांक ५ अक्टूबर, १९७१ की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमे इसे जमा किया जाता है उसका लेखा शीर्ष, के डिपोजिट एड एक्जामेंज-वीडियोजिट नाट बियरिंग इंट्रस्ट ब्रैंडर आय-रेक्ट पेंडॉ ब्रॉनीजर बियोजिट फार कास्ट आफ एम्पलाइज एंड एक्स्प्रेसेंट आपरेट ब्रैंडर बैंस्ट जर्मन कैपिटल गुड्स ब्रैंडिंग १२ फार १९८०-८१ (डी०एम० ४ बाराह ४० लाख) होगा।

5 मनीनीत जर्मन बैंक से प्राप्त नोट का पूरा विवरण देते हुए एक प्रयोगी पत्र के साथ, रिजर्व बैंक आफ ईरिया, नई दिल्ली या स्ट्रेट बैंक आफ ईरिया, नई दिल्ली मे समतुल्य रूपया नकद मे जमा करने के मामलों मे जालान की एक मूल प्रति अपके द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजी जानी चाहिए --

महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, प्रायिक कार्य विभाग,
यूसी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली।

हिमांड हाफ्ट द्वारा समतुल्य रूपया जमा करने के मामलों मे जैसा कि ऊपर की सार्वजनिक सूचना दिनांक २४ अक्टूबर, १९६८ मे जालान गया है, उसकी सूचना आर दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों मे व्याज की जो धनराशि चुका दी गई है और जिस अवधि के लिए व्याज परिशित किया गया है उसके विवरण के साथ जमा किया गा समतुल्य रूपये का पूरा विवरण इस विभाग को भेज देना चाहिए।

6 खोले जाने वाले साल्ल पक्का मे इस सबर्थ मे एक भुगतान वाक्यांश जोड़ा जाना चाहिए कि विवेशी ओमा कंपनी द्वारा प्राप्त कोई वावा और/या गारन्टी के नियादन मे समतित बैंक गारन्टी से होने वाले कोई दावे ओमा कंपनी ओर/या डी०एम० मे गारन्टी देने वाले बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय, प्रायिक कार्य विभाग, नई विल्ली को प्रबंधत करते हुए (सीधे ही के एक इम्प्ली (लेखा संखा ५०४ ०९१०० ब्यूम्बे बन्देस्वक, फैक्टरी/मेन) को प्रेषित किए जाने चाहिए।

भवदीय

लेखा अधिकारी

प्राधिकार पक्का की संख्या भी एक प्रति के साथ प्रति सूचना एवं उसके ऊपर दिए गए पक्का के संबर्थ मे मर्यादी को प्रेषित।

अनुच्छेद—६

प्रति

1. जिस आयानक/लाइसेंसदारी की ओर से बैंक गारन्टी भेजी गई थी उसका नाम और पूरा पता।

2. आयान लाइसेम की संख्या और दिनांक एवं मन्त्र।

3. भेजी गई गारन्टी की संख्या, दिनांक एवं धनराशि।

4. साक्षपत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त प्राधिकारपत्र के बौरे --

(क) प्राधिकारपत्र की संख्या एवं दिनांक

(ख) प्राधिकार पक्का की धनराशि (विदेशी मुदा मे)

5. प्रभावी किए आपातो एवं जमा किए गए रूपयो के बौरे: -

(क) संभरक का नाम

(६) उपर्युक्त (क) में जलसंधित संभरक को चुकाई गई वास्तविक धनराशि (विवेशी मुद्रा में)

(क) बेस्ट एवं बेस्ट द्वारा संभरक को किए गए सुमतान के तारीख

(द) जमा किए गए इयाज की घनराशि—

- (१) संभरक को चुकाई नहीं विवेशी मुद्रा की धनराशि का समतुल्य रूपण (विवेशी मुद्रा की एक एकक की दर से)
- (२) चुकाया गया इयाज
- (३) जिस अवधि तक इयाज परिकलित किया गया है....
- से तक।
- (४) कुल इयाज नया जमा
- (५) जमा करने का दिनांक और स्थान।

(६) राजकोष चालान की संख्या एवं दिनांक (इसे संलग्न किया जाना है) यदि राजकोष चालान पढ़ने ही ऐसा दिया गया है तो उसकी संख्या एवं दिनांक का [संश्लिष्ट उद्धृत किया जाए।

(७) यदि उपर्युक्त (ब) (४) में लिखित इयाज हिमांड ड्राफ्ट के आधार से जमा किया गया था तो ड्राफ्ट की संख्या दिनांक और घनराशि और आप के जिस पद के साथ यह महालेश्वाराल, केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया था उसके ब्यारे का उल्लेख किया जाव।

6. प्रत्येक प्राधिकारपत्र के महे प्रथम एवं उपर्युक्त लेख घनराशि (विवेशी मुद्रा में)

7. इस संबंध में एक प्रमाणात्र की उपर्युक्त कड़िका—६ में संकेतित लेख घनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और इसके लिए कोई प्रतिलिपान नहीं किया गया है तबा उसे समान हृषा समझा जाए।

(प्राधिकृत हृषालार)

प्रावधान—७

| प्रपत्र | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| कंपनी का नाम | नियंत्री कोक्ष/ सर्वेजनिक लेख | उच्चोग की श्रेणी | कंपनी की पता | प्रावेदन की घनराशि (रूपण) | आयात लाइसेंस की संख्या विवेशी मुद्रा में | संविदा का रूपण (विवेशी मुद्रा में) | सम्बन्धित कावाराह के महे | चुकाई गई घन-राशि (विवेशी मुद्रा में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

टिप्पणी:- ई००५० १० साल के समतुल्य रूपण के आधिक आवंटन से सम्बन्धित रिपोर्ट के आधिकारिक [यदि मुद्रा की दर राजस्व (सीमा-मुद्रा) किमांड द्वारा प्रधिसूचित कर रही गई हो] [माइसेसवानी के लिए परिवेशना की प्रति के और परिवेशना के पूर्ण होने के लिए निर्धारित समय के प्रत्युत्तर के लिए विशेष प्रसार पर, यदि कोई हो तो अनुच्छन-८ के रूप में प्रधान-व्यापिक रिपोर्ट को भेजना भी आवश्यक होगा। और इसके साथ परिवेशन के पूर्ण होने तक कम से कम तीन बच्चों की आविक रिपोर्ट (दो प्रतिवेशों से) भी भेजना आवश्यक होगा।

अनुच्छन—८

प्रत्येक असंत पूर्जीकृत भाल के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति के लिए व्यापक रिपोर्ट भेजने का प्रत्यक्ष ३० जून/३१ दिसम्बर।

१. कंपनी का नाम तथा पता (प्रधान कार्यालय का पता तथा फैक्ट्री का भी पता।)
२. वह राज्य जिसमें वह स्थित है (विस्त राज्य में प्रधान कार्यालय स्थित है या उससे यह संबंधित है तो उसका नाम साफ संकेत किया जाना चाहिए।)
३. क्या वह सर्वेजनिक लेख संस्थान है या नियंत्री कोक्ष संस्थान है?
४. उच्चोग के वह शास्त्रा जिससे यह संबंधित है।
५. सारत सरकार द्वारा अनुमोदित लेडिट के अंतर्गत आवंटन का मूल्य
६. शर्तों के विविधान के विवरण के साथ परियोजना का संक्षिप्त विवरण।
७. आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक तथा मूल्य।
८. ई००५० में लाइसेंस के आवीन संविदाओं का मूल्य।
९. को ई००५० में संभरकों को भुगतान की गई घनराशि।

10 यदि आयात लाइसेंस में ऐसे धनादाता हैं तो क्या उसके उपयोग किए जाने की संभावना है। यदि ऐसे हैं तो वह कितनी है और कितनी जल्दी इसे आगे संविदा द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है।

11 समय-सारणी रखना, वास्तविक तिथियों के नाम, सारणी की तुलना और समय सारणी को परिवर्तन करने के लिए क्या कारण हैं।

12 यदि नहीं तो उसके किस्तित कारणों सहित परिवर्तित समय-सारणी।

13 परियोजना की प्रगति:—

| | |
|------------------|---|
| (1) भाल का संभरण | (मुपुर्वी की गति) |
| (2) स्थापना | (फिरम तका कोटि) |
| (3) प्रचालन | (अनिम स्थाहनी, किए गए प्रयोग संबंधित के परिणाम) |

14 परियोजना की समापन तिथि

15 परियोजना की आर्थिक उपलब्धियों

16 डेविट और चिल्ड्रन बोर्ड का कार्यालयन
मोर्कन को वास्तविक यूल्य के साथ तुलना

17 परियोजना के भाल करने से संबंधित कोई विशेष घटनाएँ

18 परियोजना की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतिवर्ष)
टिप्पणी — जो लागू न हो उसे काट दें।

**MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
Public Notice No. 43-ITC(PN)/80**

New Delhi, the 12th November, 1980

Subject : Licensing conditions pertaining to West German Capital Goods Credit of 1980-81.

File No. IPC/23(10)/80.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the West German Capital Goods Credit of 1980-81 as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYAN SWAMI,
Chief Controller of Imports and Exports.

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 43-ITC(PN)/80 DATED : THE 12TH NOVEMBER, 1980

Conditions attached to Import Licences issued under the West German Capital Goods Credit of DM 44 million for 1980-81.

1. (i) Where the value of allocation approved by the Capital Goods Committee exceeds the rupee equivalent of DM 1 million (the rupee equivalent being determined at the exchange rate notified by the Department of Revenues (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962) the prior concurrence of the West German authorities (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) to the allocation is obligatory, and this would be obtained by the Department of Economic Affairs on the basis of the project data to be supplied by the Indian importer in the form at Annexure-I. Till such concurrence from West German authorities is communicated to the Licensing authorities (CCI&E) by the Department of Economic Affairs, no import licence can be issued in favour of the Indian importer.

(ii) The licence shall bear the superscription "DM 44 million West German Capital Goods Credit for 1980-81". The licence code for the first and second suffix will be "S/GN". These will also be repeated in the CCI&E's letter forwarding the import licence.

(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the Import Licence, except bank charges which may

be remitted through normal banking channel.—Payments towards Indian Agent's commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments however will form part of the licence value and will therefore be charged to the licence.

(iv) The goods and related services to be procured under this import licence can be imported from the Federal Republic of Germany including the Land Berlin or any other country.—The overseas supplier is, therefore, free to procure material, etc. from a third country, if found necessary, for the execution of the contract.

(v) The minimum value for which an import licence can be issued under this Credit is the rupee equivalent of DM 30,000 [rupees equivalent being calculated at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) which rate of exchange should be indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6th June, 1974 issued by the Chief Controller of Imports and Exports].

(vi) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 24 months or the last date of shipment as indicated in para 2 (xii) below, whichever is less, subject however to the condition that the import licence will have a minimum validity of 12 months from the date of issue.

(vii) Firm orders (meaning thereby purchase Order by the Indian Licensee on the foreign supplier supported by order confirmation from the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the foreign supplier) must be finalised within a period of 4 months from the date of issue of the import licence [vide para 1 (ix) below]. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

(viii) If firm orders, as explained in Para 1 (vii) above, cannot be finalised within the time limit of four months, the licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E), or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period along with justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the Licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence, such proposals

will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (EEC-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and convey its decision, to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of such letters of the licensing authorities sanctioning extension, will be authorised dealers in foreign exchange and departmental authorities permit the facility of bank guarantee, letters of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of rupee equivalent, etc.

(ix) It will be in the interest of the licensee to ensure that firm order is finalised within the stipulated time limit for ordering. In cases where this cannot be done the licensee should, of his own, approach the licensing authorities for a suitable extension in the period of ordering. The authorised dealers in foreign exchange/departmental authorities concerned will exercise necessary checks to ensure that the licensee complies with the requirements of placing orders within 4 months.

(x) In cases where firm orders have not been placed for the full value of the licence during the initial validity period of the licence, it will be necessary for the licensee to obtain the permission of the licensing authorities in the manner as explained in para I(viii) above before placing orders against such unorderd balance value of the licence.

Section 2 : Special points to be kept in view concluding purchases contracts.

2. (i) The contract price should invariably be expressed in the currency of the country in which the foreign supplier is situated. The contract price should be firm and final and no provision for any escalation would be permitted. If any commission is payable to an Indian Agent of the foreign supplier it must be distinctly shown in the contract as an item of cost payable in Indian rupees in India and the net amount payable to the foreign supplier in foreign currency should therefore be shown exclusive of such Indian Agent's commission. For the purpose of calculating the value in foreign exchange upto which purchase orders can be placed against the import licence, the value of the import licence should be computed at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act 1962 and indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6th June, 1974 issued by the Chief Controller of Imports and Exports.

(ii) Supply orders should be placed either on CIF or on C&F basis in the case of private sector importers. In the case of public sector importers the orders should be placed only on C&F basis.

(iii) It should clearly be understood that the purchase contracts under the import licence should be placed after obtaining comparable bids from overseas suppliers. In this connection, it may be noted that the Indian importer is free to import from any country of his choice, as approved by the Capital Goods Committee of the Government of India.

(iv) Minimum value of eligible contract.—provided that the aggregate value of purchase contracts under an import licence is not less than DM 30,000 (in the case of purchases made wholly from the Federal Republic of Germany) or equivalent of DM 30,000 (in the case of purchases made wholly or partly from countries other than the Federal Republic of Germany), it is permissible for the importer to enter into individual purchase contracts for a value of less than DM 30,000 or equivalent of DM 30,000. This is however subject to the condition prescribed in para 2(xiii) below in respect of purchase contracts under an import licence the value of which does not exceed the rupee equivalent of DM 1 million.

(v)(a) The purchase contract under the import licence is required to be specifically approved by the Government of India the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) (the West German Bank Development Loan Corporation through which the West German Capital Goods Credit of DM 44 million has been made available) and therefore should incorporate a specific clause to this effect in the purchase contract.

(b) In the case of contracts entered into against an import licence whose values is the rupee equivalent of DM 1 million or less (calculated at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs)), the approval of the contracts will not be specifically, intimated to the importer. Once the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs have forwarded the contract documents to the KfW under intimation to the importer, he may proceed as if the contract has been approved by the KfW also unless the KfW raises any objection subsequently in which event the importer will be informed suitably.

(c) In the case of contracts entered into against an import licence whose value is for an amount exceeding the rupee equivalent of DM 1 million [calculated at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)], the approval of the KfW will be first obtained by the Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs and specifically communicated to the Indian importer and until then the contracts should be treated as provisional. For this purpose 3 copies of the purchase contract along with a certificate (in triplicate) that orders have been placed after obtaining comparable bids from foreign suppliers are required to be sent by the Indian importers to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (EEC-I Section, Room No. 69, North Block) within a fortnight from the date of conclusion of the purchase contract.

(vi) Where contract is placed on CIF basis and accordingly the foreign supplier takes out the marine insurance, the foreign supplier should arrange to take out insurance in a freely convertible currency and obtain an undertaking from the insurance company concerned that payment if any arising out of insurance claims would be made directly in DM to KfW (Ac/No. 50409100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main).

(vii) Where contracts are placed on C&F basis the marine insurance should be taken out with an Indian insurance company and the premium should accordingly be paid in Indian Rupees. However the Indian importer should obtain the following undertaking from the Indian insurance company and furnish it (in triplicate) to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (EEC-I Section) along with the contract documents :—

“We shall make remittance in foreign currency to the overseas suppliers for any replacement, that may be necessitated by loss or damage to goods.”

(viii) As the contracts are required to be placed either on CIF basis or on C&F basis as per para 2(i) above, the foreign suppliers should be made responsible to pay the freight charges in foreign currency, even where Indian ships are used. In no circumstances the freight charges should be paid in Indian rupees.

(ix) Payments to foreign suppliers against the licence will be made by means of a 'Special' letter of credit as explained in Section III below and no remittance facility will be permitted against the import licence for this purpose.

(x) As regards transportation of goods purchased against the import licence the party responsible for arranging shipment of the goods under the purchase contract will be free to choose the carriers. Shipment can be made from the country in which suppliers are situated or from a third country.

(xi) For contracts whose value exceeds DM 1 million in the case of purchases from the Federal Republic of Germany including Land Berlin or, in the case of purchases from other countries, for contracts the DM equivalent of whose value exceeds DM 1 million, the purchase contracts should provide for furnishing of performance guarantee by the foreign supplier in regard to the performance of the goods supplied. (In the case of other contracts, namely for contracts whose value is less than the limit indicated above, the Indian importer is free to decide the question whether or not he needs a performance guarantee from the foreign supplier). The form of the performance guarantee can however be settled by the Indian importer with the foreign supplier by mutual consent. It should, however, be ensured by the Indian importer that payments, if any, due to him from the foreign supplier arising from the performance guarantee stipulations should be made direct to Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Acct. No. 504 09100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main).

(xii) Payments to the foreign suppliers under the import licence should be completed by the 31-12-1983. A suitable provision should, therefore, be made in the purchase orders/ contracts to ensure completion of shipments and payments by 31-12-1983. In case it is anticipated that payments cannot be completed by that date, a request for extension with adequate justification must be made to the Department of Economic Affairs (Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi) by 31-10-1983. Such request will be considered on merits.

(xiii) In the case of import licences whose value does not exceed the rupee equivalent of DM 1 million, the purchase contracts are required to be submitted by the Indian importer to the Department of Economic Affairs in a single lot. Submission of contracts piecemeal will not be entertained. In this connection the minimum value for eligible contracts explained in para 2(iv) above should be kept in view.

Section III—Payment to foreign suppliers—"Special" Letter of Credit Procedure.

(i) Request for issue of Letter of Authority.

Within a fortnight of conclusion of purchase contracts with foreign suppliers against an import licence whose value does not exceed rupee equivalent of DM 1 million (at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) or within a fortnight from the date of communication of the Government of India (vide para 2(v)(c) above) conveying the approval of KfW to the contracts placed against an import licence whose value exceed the rupee equivalent of DM 1 million (at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs), as the case may be, the licensee should submit the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, EEC-I Section, North Block, New Delhi with the request for the issue of Letter of Authority for opening an irrevocable letter of credit in favour of the foreign supplier concerned.

(a) In respect of contracts against import licence whose value does not exceed the rupee equivalent of DM 1 million.

- (i) Three copies of the Purchase Order, and three copies of the foreign supplier's confirmation thereto, duly signed by the Importer and Suppliers respectively or photo copies thereof. Attested copies of the orders placed on the Indian Agents and confirmed by such agents are not acceptable.

OR

Three copies of the purchase contract duly signed by both the Indian importer and the foreign supplier or photo copies thereof. Attested copies of the orders placed on the Indian Agents and confirmed by such Agents are not acceptable ;

- (ii) A request (in triplicate) for issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexure-JI.

- (iii) A Bank Guarantee in the prescribed form as in Annexure-III from an Indian Bank authorised to deal in foreign exchange. (not applicable in the case of Public Sector imports);

- (iv) In the case of C&F contract, three copies of the undertaking from the Indian insurance company vide para 2(vii) above;

- (v) A certificate in triplicate vide para 2(iii) above that orders have been placed after obtaining comparable bids from foreign supplier ; and

- (vi) A certificate that no further contracts will be placed under licence vide para 2(xiii) above.

(b) In respect of contracts against import licence whose value exceeds the rupee equivalent of DM 1 million.

In addition to the contract documents furnished earlier (in respect of which KfW's approval will have been obtained by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) vide para 2(v)(c) above, the following documents should be submitted :

- (i) A request (in duplicate) for the issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexure-II,

- (ii) A Bank Guarantee in the prescribed form as in Annexure-III from an Indian bank authorised to deal in foreign exchange. (not applicable in the case of Public Sector imports); and

- (iii) In the case of C&F contract, three copies of the undertaking from the Indian insurance company vide para 2(vii) above.

- (ii) It is clarified that in the case of public sector imports, no bank guarantee is required.

- (iii) **Opening of Letter of Credit.**—Letter of Credit can be opened on the strength of the Letter of Authority on any one of the following 8 commercial banks in West Germany designated for this purpose :—

- (i) The Bayertische Vereinsbank, Munich.
- (ii) The Commerz Bank A.G. Frankfurt.
- (iii) The Deutsche Bank A.G. Hamburg.
- (iv) The Dresdner Bank A.G., Jungfernstieg, Hamburg.
- (v) Berliner Handels Gasellschaft Frankfurter Bank.
- (vi) State Bank of India, Frankfurt.
- (vii) Vereins-Und-West Bank, Hamburg.
- (viii) Bank für Gemeins-Wirtschaft (Bfg).

The importers (both in the public sector and private sectors) and their bankers should specifically indicate the Bank selected by them out of the eight banks mentioned in para 3(iii) above.

- (iv) Failure to make the request for issue of Letter of Authority within a fortnight (a) from the date of placement of firm orders in the case of orders against an import licence whose value is the rupee equivalent of DM 1 million or less or (b) from the date of communication of approval of contract by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the case of contracts against an import licence whose value exceeds the rupee equivalent of DM 1 million, as the case may be, may be deemed to be a violation of the Import Control Regulations.

- (v) **Bank Guarantee—amount for which it should be executed.**

The Bank Guarantee, where necessary, should be for an amount representing the rupee equivalent of the amount in foreign exchange for which the Letter of Authority is sought plus 1 per cent of that amount towards incidental and commitment charges and in addition interest and other charges as mentioned in Annexure-V. The prevailing rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of Customs Act, 1962 and indicated in the import licence as per para 2 of Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6th June, 1974. This rate is meant only for purpose of arriving at the value of bank guarantee to be furnished by the importer. For purposes of making rupee deposits into Government account towards the foreign exchange cost of imports made under the licence the rupee equivalent will have to be worked out at the composite rate for the D.M. amounts spent by the designated commercial banks in West Germany in arranging payments to the foreign suppliers i.e. either in DM if the foreign supplier is situated in West Germany (including Land Berlin) or the DM amount for effecting payment in the currency of any other country in which the foreign supplier is located, in terms of the Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972 and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21st July, 1972 and 8-ITC(PN)/76 dated 17th January, 1976 as amended from time to time. Any change in this regard will be notified as and when necessary.

(vi) Issue of Letter of Authority.

If the documents specified in para 3(i) above are found to be in order, the Ministry of Finance (Controller of Aid Accounts & Audit), Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi will issue a letter of authority to the designated commercial Bank in West Germany (as in Annexure-IV) authorising payment upto the specified amount to the foreign suppliers on the basis of a "special" letter of credit to be opened by the importer's bank in India on the nominated commercial bank in

West Germany. A copy of such authorisation will be sent to Indian licensee. The original Letter of Authority along with a copy thereof will be sent to the concerned Indian bank authorised to open the Letter of Credit, asking it to submit the original Letter of Authority to the designated commercial bank in West Germany along with Letter of Credit opened by it. (such a direction will be as in Annexure-V). A copy of this communication will also be addressed to the importer.

No Bank in India should provide facilities to the licensee for establishing a Letter of Credit unless a Letter of Authority as explained in this para has been received by such a Bank directed from the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

(vii) The "Special" Letter of Credit on the designated commercial Bank in West Germany should be opened within thirty days from the date of the issue of Letter of Authority under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Buildings, Parliament Street, New Delhi. Otherwise the Letter of Authority already issued will be deemed to be no longer valid.

(viii) The payments to the foreign suppliers will be made by the designated Commercial Bank in West Germany on collection of requisite documents and statements. Even where the foreign supplier is situated in a country other than the Federal Republic of Germany (including Land Berlin) the negotiation and payment of documents would be done by the designated commercial bank in West Germany. The designated commercial bank in West Germany will obtain reimbursement of the DM amounts from the West German authorities. In the case of supplies by countries other than the Federal Republic of Germany, the designated commercial bank in West Germany will obtain reimbursement from the West German authorities of the amounts in DM spent by it to make the payments to the overseas suppliers in the currency of the country in which they are located.

(ix) Incidental Bank charges incurred by the both for payment in the Federal Republic of Germany as well as for arranging the payment in third country wherever applicable will be remitted by the concerned bank in India to the designated commercial bank in West Germany through the normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section IV—Responsibility for Rupees Deposits into Government Account

(i) The original shipping documents should invariably be forwarded by the designated commercial Bank in West Germany both in the case of imports from West Germany including Land Berlin and other countries, to the concerned bank in India who should, within 10 days of the receipt of the documents, release these negotiable set of documents to the licensee but only after ensuring that the rupee equivalent of DM amount paid to the German supplier or the DM amount spent in arranging the payment to the supplier in third country by the designated commercial bank in West Germany plus 1 per cent thereof towards incidental and commitment charges, together with interest charges on the above aggregate amount for the period from the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit of the rupee equivalent into Government account (both days inclusive) is recovered from the importer and deposited into Government account. In terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated the 16th June, 1976, the interest charges are to be calculated as under in respect of deposits made into the Government Account on or after 15th June, 1976.

| | |
|---|-----------------|
| (i) where deposits are made within 30 days after from the date of payment to the supplier. | 9 % per annum. |
| (ii) where rupee deposits are made more than 30 days after the date of payment to the supplier. | |
| (a) for the first 30 days | 9 % per annum |
| (b) for period in excess of 30 days | 15 % per annum. |

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the foreign currency payments made to the foreign supplier will be the composite rate of exchange as laid down in CCI&E's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17th January, 1976 or as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through the Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the original shipping documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

(ii) The deposits envisaged in para 4(i) above may be made in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not feasible, the amounts may be remitted by means of a demand draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC(PN)/68, dated the 24th October, 1968 as amended vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 and Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated the 5th October, 1971. The Head of Account to be credited is : "K-Deposits and advances—Deposits not bearing interest—843-Civil Deposits—Deposits for purchases etc. abroad—Direct Payment Procedure Deposits for cost of supplies and equipment obtained under the West German Capital Goods Credit XII for 1980-81 (DM 44 million Credit)".

(iii) Remittance will be made in the Challan form prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated the 31st May, 1974.

(iv) One copy of the Challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 or intimation regarding the submission of Demand Draft to the State Bank of India Tis Hazari, Delhi-6 should be sent by the Indian Bank, which had issued the guarantee, to the Controller of Aid Accounts & Audit Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi along with a forwarding letter, giving full details of the Advice Notes received from the concerned nominated German bank.

(v) It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them, as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated the 30th August, 1968. They should also fill in the requisite "S" forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

(vi) After the imports under a licence are completed and the importers/banks have deposited into Government account all the amounts due, details of the imports received and of rupee deposits made should be furnished to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, New Delhi-1 in the proforma prescribed as Annexure-VI to enable the Ministry of Finance to verify and arrange for release of the bank guarantee furnished by the importers, wherever necessary.

Section V—Alteration in the contract

Any material alteration in the contracts pertaining to the list of goods, terms or schedule of payments, value of goods, etc. will require the prior approval of the Ministry of Finance and the KfW authorities, whether it results in earlier payments, or in postponement of payments.

Such alteration(s) should be promptly intimated by the importer to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi (EEC-I Section, North Block) for securing the approval of the Government of India/KfW in the same manner as explained in para 2(v) above.

Section VI—Reporting

A quarterly report commencing from the date of issue of the licence should be furnished in duplicate as in Annexure-VII to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (EEC-I Section Room No. 69, North Block), New Delhi showing progress of ordering, delivery of goods,

payments to foreign suppliers, etc. and should be continued till all shipments and payments under the contract have been completed. In the case of allocation exceeding the rupee equivalent of DM 1 million (at the exchange rate) notified by the Department of Revenue (Customs) the licensee should, in addition to the above mentioned quarterly reports, submit a half-yearly report as on 30th June and 31st December each year in the prescribed proforma at Annexure-VIII (duplicate) on special event, if any, on the progress of the project and on adherence to the time-schedule for completion of project alongwith Annual Report (2 copies) of the Indian importing company for at least three years until completion of the project.

Section VII—Miscellaneous Provisions

7. (i) The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the Suppliers in carrying out the transactions.

(ii) Disputes.

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes if any that may arise between the Indian importers and the foreign supplier.

(iii) Compliance with Instructions.

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence for meeting all obligations under the DM 44 million Capital Goods Agreement with KfW authorities.

(iv) Breach or Violations.

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

(v) List of Annexures :

| | |
|----------------------|---|
| Annexure I | Project data Form. |
| Annexure II | Form of Request for issue of Letter of Authority. |
| Annexure III | Form of Bank Guarantee. |
| Annexure IV | Form of Letter of Authority. |
| Annexure V | Letter of Instructions forwarding the Letter of Authority. |
| Annexure VI | Form of report of rupee deposits-cum-application for release of Bank Guarantee. |
| Annexure VII | Form for submitting quarterly report. |
| Annexure VIII | Form of Half-yearly Progress Report (applicable to cases exceeding rupee equivalent of DM 1 Million). |

ANNEXURE I

PROJECT DATA FORM

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU

6, Frankfurt/Main, Federal Republic of Germany Palmen-gartenstrasse 5-9

Application for Foreign Exchange from German Capital Goods Loan

PROJECT DATA

(1) Applicant (Firm)

- (a) Registered Office (address incl. State)
- (b) Public Sector or private sector undertaking.
- (c) Business Line/Branch of Industry.

(d) Partners of Company.

(e) Foreign Collaboration Agreement.

(2) Type of Capital Goods to be financed.

(3) Choice of capital goods based on—please indicate the procurement procedure followed. Since the Capital Goods loan is available for purchases from any country, an indication should be given whether tender enquiries were made/floated in various countries and the basis on which the selection of a particular supplier has been made.

(4) Suppliers (name and address).

(5) Short description of the whole project (for which such capital goods are required).

(6) Local and foreign exchange cost of the whole Project, with following break-down of figures

- Land and building
- Machinery and equipment
- Operating Funds
- Miscellaneous

(7) Local and foreign financial sources for the whole project (Quantitative statement concerning means of financing. It should be confirmed that Rupee-financing is secured and that foreign exchange requirements not covered by this application are met).

(8) Letter of Intent for Industrial Licence received

(9) Annual reports with balance sheets and profit and loss accounts for the last two years. If available forecast of cash-flow and profitability.

(10) Capacity

(a) Average utilization of existing capacity during the last two years.

(b) In case of underutilisation, please give main reasons.

(11) Sales (last two years).

(12) Market position of the products to be manufactured (if possible figures showing past and expected development).

(13) Employment

(a) Present number of employees.

(b) Additional employment after completion of project.

(14) Source of raw material supplies.

(15) Time-table for the execution of the project.

ANNEXURE II

REQUEST FOR ISSUE OF LETTER OF AUTHORITY

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building,
Parliament Street, New Delhi 110001.

Subject : Import of _____ from _____ under
West German Capital Goods Credit for 1980-81 (DM
44 million Credit).

Sir,

In connection with the import of _____ from _____ under the above mentioned West German Capital Goods Credit, we furnish the following particulars to enable you to issue the authority for opening the letter of credit through _____ on the Bayerische Vereinsbank, Munich, or Commerzbank A.G. Frankfurt or Deutsche Bank, A.G. Hamburg or the Dresdner Bank, A.G. Jungfernstieg, Hamburg or the Frankfurter Bank, Frankfurt A.M Main or State Bank of India, Frankfurt or Vereins-Und West Bank, Hamburg or Bank fur Gemeins-Wirtschaft (Bfg).

Name and Address of the Importer.

- (i) Whether a public or private sector undertaking.
- (ii) Category of industry to which it belongs.
- (iii) The State in which it is located.
- (b) Number, date and value of licence, (photostat copy of the licence should be attached).
- (c) Value in foreign currency and date of the order placed and accepted by the suppliers, indicating payment terms viz., (c.i.f. or C&F) (In no case, Letter of Authority should be applied for f.o.b. value only).
- (d) A certificate in duplicate that firm order (with suppliers order confirmation) have been placed within a period of 4 months from the date of import licence. If orders have been placed after the stipulated period of 4 months, a copy of CCI&E's letter/Ministry of Finance's letter authorising extension of time for placing firm orders as the case may be, should be attached.
- (e) A certificate in triplicate that firm orders have been placed after obtaining comparable bids from overseas suppliers and that the lowest technically suitable offer has been accepted. In case it is not possible to obtain comparable bids, e.g. proprietary item, full justification therefor should be furnished.
- (f) Short description of the goods to be imported.
- (g) Net foreign currency amount payable to Suppliers (to be expressed in the currency of the country in which supplier is located) for which letter of Authority is required (excluding Agency commission).
- (h) Amount of agency commission in foreign currency and name and address of Indian Agent.
- (i) In case the supplier happens to be located in a country other than West Germany, the name of the suppliers' bank to whom the amount is to be remitted by the designated Commercial Bank in West Germany should be indicated.
- (j) Expected date of completion of delivery.
- (k) A schedule showing probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) In the case of import licence upto a value which is equivalent to DM 1 million, a certificate that all the contracts against the import licence have been placed and that no further contract will be placed.

The Letter of Credit will be opened through _____

(Name and address of the Indian scheduled bank, authorised to deal in foreign exchange)

and the Bank Guarantee No. _____ dated _____ for Rs. _____ furnished by the above mentioned bank and which has been fully adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the Stamps Act, 1899 is attached.

Yours faithfully

(Licensee)

Copy forwarded to _____ Bank for information.

ANNEXURE III

GUARANTEE BOND

President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called the Government) having agreed to arrange for payment in (mention the appropriate amount in foreign currency) for the import of _____ by _____

(hereinafter called the 'importer') against the licence No. _____ dated _____ issued under the terms and conditions of West German Capital Goods Credit for 1980-81 and in pursuance of import in favour of the importer against the abovementioned agreement, we _____ Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amount of the disbursements made by the _____ (Name of the commercial Bank nominated by the importer in West Germany) converted at the prevailing rate of exchange calculated as per instructions issued by the Government in the matter from time to time plus 1 per cent thereon within 10 days of the receipt of advice of payments, for credit to the Government account, in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by Government of India under the said credit together with interest thereon at the rates of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit of rupee equivalent for credit into the Government account. The negotiable set of import documents received from the designated commercial Bank in West Germany will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the _____ Bank also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Govt. may from time to time direct, such sums not exceeding Rs. _____ or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereupon at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 5 per cent per annum for the period in excess thereof, reckoned from the date of payment to the foreign supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us _____ Bank shall be final and binding on us _____ Bank.

3. We _____ Bank further agree that in case of increase in the value of imports or decrease in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion to this change.

We _____ Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement/Contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claim satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be effected by any change in the constitution of the importer or the _____ Bank and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the power exercisable by it against the importer and the _____ Bank shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reasons of time being given to the Importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the importer or by any other matter or things whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the _____ Bank from its such liability.

6. We _____ Bank lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government in writing.

7 Our liability under this guarantee is restricted to Rs. _____ (plus interest and other charges not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount) and it will remain in force till the _____ day of _____ (month) _____ 19_____. Unless claims under the guarantee are made in writing within

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated the 24th October, 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the Address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

6. A payment clause to the effect that the insurance claim, if any, received from the foreign Insurance company and/or claims, if any, arising out of Bank Guarantee relative to performance guarantee should be remitted by the Insurance Company and/or the Bank giving the guarantee in DM direct to KfW (Account No. 504:09100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main) under advice to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi, may be inserted in the Letter of Credit to be opened by you.

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to M/s. _____ with a copy of the Letter of Authority No. _____ for information, with reference to their letter quoted above.

Accounts Officer

ANNEXURE VI

Proforma

1. Name and full address of the importer/licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.
2. The import licence number and date and value.
3. Number, date and amount of the guarantee furnished.
4. Particulars of the Letter of Authority for opening Letter of Credit obtained from the Ministry of Finance.

(a) Number and date of the Letter of Authority.

(b) Amount of the Letter of Authority (in foreign currency).

5. Particulars of Imports effected and rupee deposits made.

(a) name of suppliers.

(b) Amount (in foreign currency) actually paid to the supplier(s) mentioned at (a) above.

(c) Date of payment to the supplier by the nominated Bank in West Germany.

(d) Amount of rupee deposits :

(i) Rupee equivalent of foreign currency amount paid to the supplier @ 1 unit of foreign exchange = Rs. _____

(ii) Interest paid.

(iii) Period for which the interest has been calculated from _____

(iv) Total Deposit made.

(v) Date and place of deposit.

(vi) Number and date of the Treasury Challan (to be enclosed). If the Treasury Challan has already been sent, reference to the letter number and date with which it was sent may be quoted.

(vii) If the rupee deposit mentioned in (d)(iv) above was made by means of Demand Draft, the number, date and amount of the draft and particulars of your letter with which it was sent to the Accountant General, Central Revenues, to be indicated.

6. Amount utilised and balance unutilised (in foreign currency) against each Letter of Authority :—

7. A certificate that the balance indicated in 6 above has not been utilised and no shipment has been made thereof, and the same may be treated as lapsed.

(Authorised signatories)

ANNEXURE—VII

PROFORMA

| Name of Company | Private Sector/ Public Sector | Category of Industry | Address of Company | Amount of allocation (Rs.) | No. date and value of I.L. | Value of contract (Foreign currency) | Value of L.C. | Amount paid against the LC (Foreign currency) |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Note : In respect of allocation exceeding the rupee equivalent of DM 1 million (If the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs), the licensee will be required to submit in addition half yearly report as in Annexure-VIII on special event, if any, on the progress of the project and on adherence to the time-schedule for completion of project alongwith Annual Report (2 copies) for at least three years until completion of the project.

ANNEXURE—VIII

Proforma for Submission of Half-year reports on progress of Projects Financed under West German capital Goods Credits—30th June/ 31st December.

1. Name of Company and address (Address of Head Office and also address of factory).
2. State in which it is located (if the factory is located in State other than the State in which the Head Office is located, it should be clearly indicated).

3. Whether a public sector or private sector undertaking.
4. Branch of Industry to which it belongs.
5. Value of allocation under the credit approved by the Government of India.
6. Brief Description of the Project including description of the Capital Goods items of manufacture.
7. No., date and value of the import licence.
8. Value of supply contract (s) under the licence in DM.
9. Amount paid to the Suppliers as on _____ in D.M.
10. If there is a balance in the import licence, whether it is likely to be utilised. If so, how much and how soon it is going to be utilised by further contracting.
11. Keeping of time schedule comparison of schedule with actual dates, reasons for changing the time schedule.
12. If not, revised time-table with detailed reasons therefor.
13. Progress of the Project

| | |
|-------------------------|--|
| (i) Supply of the goods | (terms of delivery) |
| (ii) Erection | (kind and quality) |
| (iii) Commissioning | (final acceptance, trial runs results of operation). |
14. Date of completion of the Project.
15. Economic implication of the project.
16. Realisation of the Cost and Finance Plan comparison of plan with actual values.
17. Any special events connected with the implementation of the project.
18. Latest annual report of the Project Sponsor (2 copies).

N.B. : Strike out the portions not applicable.

